भारत में विमुद्रीकरण (विमुद्रीकरण : समस्या नहीं..... एक समाधान)

प्रीति कुशवाह

प्रस्तावना :

विमुद्रीकरण :

विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत किसी देश की सरकार अपने देश की पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर समाप्त कर नई मुद्रा से उसे प्रतिस्थापित कर देती है। जब अर्थव्यवस्था में काला धन बढ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इस खतरे के समाधान के रूप में इस विधि को प्रयोग में लाया जाता है जिसके फलस्वरूप जिनके पास काला धन होता है वे उस कालेधन के बदले नई मुद्रा को लेने का साहस नहीं कर पाते और इस तरह कालाधन स्वतः ही नष्ट हो जाता है।

विमुद्रीकरण के बाद पुरानी मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाती,उससे किसी तरह की खरीद–फरोख्त नहीं की जा सकती। जब सरकार द्वारा विमुद्रीकरण किया जाता है तो सरकार बंद किये गये पुराने नोटों को बैंक में जमा कर उनकी जगह नये नोट लेने की समय सीमा तय कर देती है जिससे पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा चलन में आ जाती है।

विमुद्रीकरण की आवश्यकता के कारण :

किसी भी देश की सरकार द्वारा देश में प्रचलित विभिन्न मुल्य वर्ग के नोटों में से किसी विशेष वर्ग के नोटों जो सामान्यतः बड़े मूल्य वर्ग के नोटों को प्रतिबंधित करने के अनेक कारण हो सकते है। जैसे :–

- मुद्रा की जमाखोरी (कालाधन) समाप्त करने हेतु।
- आतंकवाद, अपराध तथा तस्करी जैसे आपराधिक कार्यों को रोकने हेतु।
- बाजार में प्रचलित नकली नोटों से छुटकारा पाने हेतु।
- जालसाजी से बचने के लिए नई तकनीकी से तैयार किये गये ज्यादा सुरक्षित नोट अर्थव्यवस्था में लाने हेतु।
- टैक्स की चोरी के लिए किये जाने वाले नगद लेन–देन को हतोत्साहित करने हेतु।

अनुमान लगाया गया था कि देश की अर्थव्यवस्था में विमुद्रीकरण से पहले लगभग 400 करोड़ रूपए के नकली नोट चलन में थे अर्थात् प्रत्येक 10 लाख नोटों में 250 नकली नोट शामिल थे। इसी दिशा में नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा उठाया गया विमुद्रीकरण का कदम एक सफल प्रयास कहा जा सकता है।

भारत में विमुद्रीकरण का इतिहास :

1. 12 जनवरी सन् 1946 में :–

भारत में पहली बार सन् 1946 में सरकार द्वारा 1000 और 10000 रूपए के नोटों को अर्थव्यवस्था से समाप्त कर दिया। सन् 1934 में 500 व 1000 रूपए के नोट प्रचलन में आये तथा इसके 04 साल बाद 10000 रूपए के नोट प्रचलित किये गये। 5000 रूए के नये नोट 1954 में शुरू किये गये थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक 10000 रूपए से अधिक का नोट जारी नहीं किया है। इसके पश्चात् सन् 1970 के दशक में "प्रत्यक्ष कर की जाँच" से जुड़ी "वान्चू समिति" ने कालाधन बाहर लाने तथा उसे समाप्त करने हेतु विमुद्रीकरण का सुझाव दिया। परन्तु इस सुझाव के सार्वजनिक को जाने के कारण अंततः विमुद्रीकरण की योजना को निरस्त करना पड़ा।

2. 16 जनवरी सन् 1978 में :–

सन् 1977 में चुनाव के बाद केन्द्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनवरी 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी ने एक कानून के तहत् 1000, 5000 और 10000 रूपए के नोटों का विमुद्रीकरण किया ताकि जालसाजी तथा कालेधन पर अंकुश लगाया जा सके। सन् 1987 में आरबीआई द्वारा 500 रूपए के नए नोट अर्थव्यवस्था में लाए गये।

3. 08 नवम्बर 2016 में :–

08 नवम्बर 2016 को रात्रि 08 बजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा 500 तथा 1000 रूपए के नोट को बंद करने की घोषणा की गई तथा इसकी जगह 500 व 2000 के नये नोट प्रचलत में लाए गये। जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गर्वनर उर्जित पटेल ने बहुत साहसिक कदम बताया। जिसका उद्देश्य ना केवल कालेधन पर नियंत्रण की बल्कि नकली नोटों से छुटकारा पाना भी था।

31 मार्च 2016 को प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रचलित मुद्रा में नोटों की कुल कीमत 16.42 लाख करोड़ रूप्ए है। जिसमें से 86 प्रतिशत 500 तथा 1000 के नोट सम्मिलित हैं। मात्रा के आधार पर रिपोर्ट के अनुसार 9026.60 करोड़ नोटों में से 24 प्रतिशत अर्थात् 2203 करोड़ बैंक नोट प्रचलन में थे। प्रधानमंत्री मोदी की आधिकारिक घोषणा के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल तथा आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सभी मुल्यवर्ग के नोटों की आपूर्ति में 2011 और 2016 के बीच 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस अवधि में 500 व 1000 रूपए के नोटों में क्रमशः 76 प्रतिशत और 109 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी तथा इस नकली नगदी को आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रचलित नोटों को खत्म करने का निर्णय लिया गया।

विमुद्रीकरण के सकारात्मक प्रभाव :–

विमुद्रीकरण के फलस्वरूप हुई नोटबंदी से सम्पूर्ण देश की सरकार तथा अर्थव्यवस्था को अनेक फायदे प्राप्त हुये :–

1. कैशलेस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन :–

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने हेतु आवश्यक है कि उस देश में अधिक से अधिक लेन–देन डिजिटल माध्यम से किये जाए जो कि अधिक सुरक्षित तथा द्रुतगामी है। जिससे उस देश की करेंसी पर निर्भरता कम होगी।

2. नकली मुद्रा की समाप्ति :–

नकली नोटों की रोकथाम हेतु जहाँ सरकार को बड़े नेटवर्क का सहारा लेना पड़ता था वहाँ विमुद्रीकरण तथा मुद्रा के कम इस्तेमाल (डिजिटल लेन–देन के कारण) से एक झटके में देश की नकली मुद्रा साफ हो गई तथा नई मुद्रा के सुरक्षा मानक ज्यादा मजबूत होने से अगेल कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था नकली मुद्रा से सुरक्षित हो गई है।

3. काला धन समाप्त :–

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से कालेधन को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका सामाजिक स्तर पर बहिष्कार न होने लगे। विमुद्रीकरण का सबसे गहरा आघात कालेधन के कुबेरों को लगा। अनुमान था कि देश में लगभग 03 लाख करोड़ रूपए कालेधन के रूप में छिपा कर रखे गये।

4. अवैध गतिविधियों की रोकथाम में सहायक :–

अनेक आतंकवादी नशे के व्यापार, तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों को संचालित रखने के लिए देश की मुद्रा का दुरूपयोग किया जा रहा था, विमुद्रीकरण के कारण इन गतिविधियों के संचालन पर पाबंदी लगानी संभव हुई। एक तरफ जहाँ इन समूहों द्वारा जमा किये गये नोट कागज के टुकड़ों में तब्दील हो गये, वहीं नये नोटों के अभाव में इनकी गतिविधियाँ निष्क्रिय पड़ गई।

5. आय को उजागर करने में सहायक :–

विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप जनता को अपनी आय नोट परिवर्तन कराने हेतु बैंकों के पास जाना पड़ा। जिससे उनकी आय का विवरण सरकार तक पहुँचना संभव हुआ।

6. करों की प्राप्ति में वृद्धि :–

आय ज्ञात होने के कारण कर योग्य आय पर कर प्राप्त करना आसान हो गया। जिनका उपयोग सरकार आधारभूत सुविधाओं के विकास में करती हैं। सरकार ने विमुद्रीकरण के दौरान कालेधन को छिपाकर रखने वालों को कर नियम के अनुसार अपने धन का खुलासा कर, कर चुका कर उसे वैध बनाने की राहत दी जिसका असरदार लाभ देखने को मिला। सरकार की रिपोर्ट

के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद कर प्राप्ति में 14.5 फीसदी की बढ़ोतरी संभव हुई।

7. अर्थव्यवस्था में सुधार :–

विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप प्राप्त विभिन्न करों के माध्यम से सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है जिसको सरकार आधारभूत ढाँचे में निवेश कर देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करती हैं।

नकारात्मक प्रभाव :–

1. जनता में अराजकता उत्पन्न होना :–

विमुद्रीकरण के कारण जनता को बैंकों के बाहर लम्बी–लम्बी कतारों में खड़ा रहना पड़ा। जिससे जनता को आक्रोश व अराजकता कव समाना करना पड़ा।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दुष्प्रभाव :–

ग्रामीण क्षेत्रों में संचार के साधनों का अभाव होने के कारण अधिक दुष्प्रभाव देखने को मिले। जागरूकता की कमी के कारण ग्रामीण जनता को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा।

3. नोटों के मुद्रण व प्रचान हेतु अधिक व्यय :–

नये नोट छपवाने तथा उन्हें अर्थव्यवस्था में प्रसारित करने के लिये सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में व्यय करना पड़ा।

4. कृषकों द्वारा अपनी उपज को कम कीमत पर बेचने की विवशता :–

नकदी की कमी के कारण किसानों द्वारा अपनी उपज कज्ञ उचित मूल्य प्राप्त करना कठिन हो गया। जिसके कारण उपज की बर्बादी हुई तथा लागत भी प्राप्त नहीं होने के कारण किसानों ने आत्महत्यायें की।

5. पर्यटन उद्योग पर प्रभाव :–

विमुद्रीकरण के दौरान स्थानीय मुद्रा की कमी होने के कारण पर्यटकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिनमें विदेशी पर्यटकों को तुलनात्मक रूप से अधिक समस्याओं से ग्रस्त होना पड़ा। फलस्वरूप देश का पर्यटन उद्योग मंदी की चपेट में आ गया।

निष्कर्ष :–

सरकार के द्वारा किये गये विमुद्रीकरण के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही परिणाम देखने को मिलें परन्तु आंतंकवादी गतिविधियों में मुद्रा के दुरूपयोग को रोकने व कालेधन पर अँकुश लगाने हेतु सरकार के द्वारा उठाया गया यह एक ठोस कदम है। एक ओर विपक्षी दल सरकार के इस प्रयास को असफल व देश की अर्थव्यवस्था को पीछे ले जाने वाला सिद्ध करते रहें वहीं दूसरी ओर सरकार अपने निर्णय को सही साबित करने में लगी रहीं। विमुद्रीकरण के निर्णय से जहाँ समस्याओं का सामना करना पड़ा वहीं भारतीयों में भाईचारे की भावना देखने को मिली। नोटबंदी की वजह से प्राचीन समय की सफल बार्टर प्रणाली फिर से कारगर सिद्ध हुई, जनता ने बिना पैसे के भी कार्य करने सीखे। प्रधानमंत्री जी ने "नरेन्द्र मोदी एप" पर जनता से नोटबंदी पर राय मांगी जिसमें जनता का सहयोग प्राप्त हुआ। सरकार व आयकर विभाग ने कालेधन पर नियंत्रण लगाने हेतु सक्रियता से कार्य किया। कुछ अर्थशास्त्रियों कव दावा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि में कुछ समय के लिये गिरावट होगी लेकिन विमुद्रीकरण के दूरगामी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगें। इससे न केवल नकली नोट छापने के कारोबार पर अँकुश लगा अपितु उनसे संबंधित अवैध करोबार भी खत्म हो गये।

Department Of Business Administration,
UOR Jaipur